



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239319
CG-DL-E-03102022-239319

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]
No. 248]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरूआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

[मामला सं. एडी(एसएसआर) 07/2022]

विषय: चीन जन.गण. में उत्पन्न या निर्यात किए गए सिरेमिक रोलर्स के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

1. फा.सं. 7/18/2022-डीजीटीआर.—समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह) के संबंध में पाटित वस्तुओं किए गए सामानों पर पाटनरोधी शुल्क और चोट के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद "नियम" या "पाटनरोधी नियम" के रूप में भी जाना जाता है), फ्र्यूचूरा सिरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड इसके बाद इसे) "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" के रूप में भी कहा गया है) ने "सिरेमिक रोलर्स" के आयात पर पाटनरोधी शुल्क शुल्क की समीक्षा जांच के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी इसके बाद इसे ("प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। "(इसके बाद "विषय वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी) के रूप में संदर्भित किया गया है जो चीन जन.गण. में उत्पन्न या निर्यात किया गया है (इसके बाद "विषय देश" के रूप में संदर्भित)।

2. अधिनियम की धारा 9ए, (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले निरस्त नहीं किया जाता, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकरण को समीक्षा करनी होगी

कि क्या अवधि समाप्त हो गई है। शुल्क के कारण पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है। उसी के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. पूर्व जांच की पृष्ठभूमि

3. संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा 19 अप्रैल 2017 को अधिसूचना संख्या 14/52/2016-डीजीएडी के तहत शुरू की गई थी। प्राधिकरण ने अधिसूचना संख्या 14/47/2016-डीजीएडी दिनांक 26 मार्च 2018, निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 27/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 मई 2018 द्वारा लगाए गए थे। उक्त शुल्क 5 वर्षों की अवधि के लिए लगाए गए थे और 16 मई 2023 को समाप्त होने वाले हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:

"वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद "सिरेमिक रोलर्स" या "रोलर्स" (जिसे बाजार की भाषा में सिरेमिक पाइप या ट्यूब के रूप में भी जाना जाता है) है और इसका उपयोग रोलर चूल्हा भट्टों में भट्टे के एक छोर से दूसरे छोर तक टाइलों के परिवहन के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर घुमाकर रोलर्स टाइलों को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने की अनुमति देते हैं। सिरेमिक रोलर्स का उपयोग उन उद्योगों में भी किया जाता है जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने के लिए एसएस (स्टेनलेस स्टील) स्ट्रिप्स / पट्टा बनाते हैं। इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 69 के तहत वर्गीकृत किया गया है।

5. वर्तमान याचिका निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है, स्थापित न्यायशास्त्र और प्राधिकरण की पिछली प्रथाओं के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जैसा कि मूल अंतिम जांच परिणाम में परिभाषित किया गया था।

ग. विचाराधीन उत्पाद

6. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यात किए गए उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों चीजें तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमय के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा, वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क के निरंतर अधिरोपण के लिए निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है समान वस्तु के मुद्दे की प्राधिकारी द्वारा पिछली जांच में भी जांच की गई है। संबद्ध देश से आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए 'समान वस्तु' है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

7. आवेदन फ़्यूचूरा सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक होने का दावा किया है। आवेदक ने आगे प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही संबद्ध देश के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(बी) के अर्थ के अंतर्गत चीन में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत के किसी आयातक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तथापि, आवेदक ने यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तुओं की छोटी मात्रा का आयात किया है। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा किए गए आयातों की जांच की है। यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा आयात की मात्रा कम है और महत्वपूर्ण राशि नहीं है। आवेदक को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(बी) के तहत परिभाषित 'घरेलू उद्योग' के रूप में माना जा सकता है। आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

8. इसे ध्यान में रखते हुए और उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकरण संतुष्ट है कि आवेदन 'घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से' किया गया है और नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ङ. संबद्ध देश

9. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

च. पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना**सामान्य मूल्य**

10. चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (i) का हवाला दिया और उस पर भरोसा किया। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रचलित है। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि यदि प्रतिवादी चीनी निर्माता यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत की जानकारी बाजार संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुबंध। के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए। तदनुसार सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध। के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

11. आवेदक ने यूरोपीय संघ से भारत को निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया था। वैकल्पिक रूप से, आवेदक ने भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए जोड़ने के बाद भारत में देय मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए उत्पादन की लागत और बिक्री के लिए जोड़ के बाद, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

निर्यात मूल्य

12. आवेदक ने निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए बाजार आसूचना के अनुसार रिपोर्ट की गई सीआईएफ कीमत का दावा किया है। तथापि, शुरुआत के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत की गणना के लिए आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना पर भरोसा किया है। कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा खर्च, बंदरगाह खर्च और बैंक शुल्क के साथ समायोजित किया गया है।

पाटन मार्जिन

13. उपरोक्तानुसार, निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(क)(1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन केवल न्यूनतम के स्तर से अधिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमतों की तुलना में काफी अधिक है, यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों में उत्पन्न या निर्यातित संबद्ध वस्तुओं को पाटित कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है और इस प्रकार निरंतर पाटन को दर्शाता है ताकि जांच शुरू करने का औचित्य साबित करने के लिए।

छ. क्षति लगने की संभावना

14. आयात में वृद्धि, भारतीय मांग में आयातों के महत्वपूर्ण हिस्से, आयातों के दमनकारी प्रभाव, घरेलू उद्योग को हुई हानि, कम क्षमता उपयोग और कम बाजार और घरेलू उद्योग के हिस्से के कारण पाटन और परिणामी क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। डंपिंग रोधी शुल्क वर्तमान में लागू है। आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना, प्रथम दृष्टया, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की डंपिंग जारी रखने और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रखने को दर्शाती है।

ज. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

15. और इसलिए, आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, डंपिंग और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना को प्रमाणित करने के आधार पर, और धारा के अनुसार नियमों के नियम 23 (1बी) के साथ पठित अधिनियम का 9ए(5), प्राधिकरण एतद्वारा मूल रूप से या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों के निरंतर अधिरोपण की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करता है। संबद्ध देश और यह जांच करने के लिए कि क्या इस तरह के शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

16. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2021 से मार्च 2022 है। क्षति जांच अवधि 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि को कवर करेगी। पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की भी जांच की जा सकती है।

ज. प्रक्रिया

17. वर्तमान समीक्षा में अधिसूचना संख्या 14/47/2016-डीजीएडी दिनांक 26 मार्च 2018 के तहत प्रकाशित मूल जांच के अंतिम निष्कर्षों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 के प्रावधान। नियमों के 17, 18, 19 और 20 इस समीक्षा में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

18. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर, सभी संचार ईमेल पते adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुत करने का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में है और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हैं।

19. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकार, आयातकों और भारत में प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं से संबंधित होने के लिए जाना जाता है और घरेलू उद्योग को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच के लिए प्रासंगिक अपना अनुरोध ऊपर पैरा 18 में उल्लिखित ईमेल पते पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से कर सकता है।

21. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्ष के लिए आवश्यक है कि वह उसका एक अगोपनीय संस्करण अन्य पक्षों को उपलब्ध कराए।

22. इच्छुक पार्टियों को आगे यह सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए नामित प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in/> पर नियमित रूप से नजर रखें।

ठ. समय-सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को ईमेल पते adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov पर भेजी जानी चाहिए। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर। तथापि, यह नोट किया जा सकता है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाला नोटिस उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा, जिस दिन इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या इसे प्रेषित किया गया था। निर्यातक देश का उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकरण नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को दर्ज कर सकता है।

24. सभी इच्छुक पार्टियों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) को सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. प्राधिकरण के समक्ष गोपनीय आधार पर कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण या सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्ष को नियमों के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार नोटिस के अनुसार एक साथ एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफल रहने पर प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकृत की जा सकती हैं।

26. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी प्रस्तुतिकरण (संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षों को अलग-अलग गोपनीय और अगोपनीय संस्करण दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

27. प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" सबमिशन को स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकरण द्वारा अगोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पार्टियों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

28. गोपनीय संस्करण में ऐसी सभी जानकारी शामिल होगी जो स्वभाव से गोपनीय होती है और/या अन्य जानकारी जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति द्वारा गोपनीय होने का दावा किया जाता है या वह जानकारी जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, जानकारी के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

29. गैर-गोपनीय संस्करण को गोपनीय जानकारी के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसे अधिमानतः अनुक्रमित या खाली कर दिया गया है (यदि सूचीकरण संभव नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर सारांशित किया गया है जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है। गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्राप्त जानकारी के सार की उचित समझ हो सके। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और कारणों का एक विवरण क्यों सारांशित करना संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ के गैर-गोपनीय संस्करण को प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

30. प्राधिकरण प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के अनुरोध की आवश्यकता नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो सूचना को सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं है या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

31. एक सार्थक अगोपनीय संस्करण के बिना या गोपनीयता के दावे पर अच्छे कारण के बयान के बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

32. प्राधिकरण संतुष्ट होने और प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।

ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

33. नियमों के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी इच्छुक पार्टी अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के गैर-गोपनीय संस्करण वाली सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण कर सकती है। सार्वजनिक फ़ाइल को इलेक्ट्रॉनिक मोड में बनाए रखने के तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है।

ण. असहयोग

34. ऐसे मामले में जहां कोई हितबद्ध पक्ष उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी तक पहुंच से इनकार करता है या अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, प्राधिकरण अपने निष्कर्षों को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है। जैसा उचित समझा।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

[Case No. AD (SSR) 07/2022]

Subject: Initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty on the imports of Ceramic Rollers originating in or exported from China PR.

1. **F. No. 07/18/2022-DGTR.**—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or the “Anti-Dumping Rules”), Futura Ceramics Private Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or “petitioner” or “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) for sunset review investigation of anti-dumping duty on imports of “Ceramic Rollers” (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “product under consideration” or the “PUC”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. In terms of Section 9A, (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. Background of previous investigation

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority *vide* notification No.14/52/2016-DGAD on 19th April 2017. The Authority issued the final finding *vide* notification No. 14/47/2016-DGAD dated 26th March 2018, recommending the imposition of definitive anti-dumping duties, which were imposed by the Central Government *vide* Notification No. 27/2018-Customs (ADD), dated 17th May 2018. The said duties were levied for a period of 5 years and are set to expire on 16th May 2023.

B. Product under consideration

4. The product under consideration in the present investigation is the same as defined in the original investigation which is as follows:

“The product under consideration in the present petition is “Ceramic Rollers” or “Rollers” (also known as Ceramic pipes or tubes in market parlance) and is used in Roller Hearth Kilns to transport tiles from one end of the kiln to the other end. By rotating around themselves the rollers allow the tiles to be transported from one end to the other. The Ceramic Rollers are also used in Industries that make S.S. (Stainless Steel) Strips/ Patta to manufacture Stainless Steel Utensils. It is classified under Chapter 69 of the Customs Tariff Act.

5. The present petition being for sunset review investigation, as per the settled jurisprudence and the past practices of the Authority, the product under consideration remains the same as defined in the original final finding notification.

C. Like Article

6. The applicant has claimed that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject country. The product produced by the domestic industry and those imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. Further, the present application is for sunset review investigation for the continued imposition of anti-dumping duty. The issue of like article has been examined by the Authority in the previous investigations as well. The product imported from the subject country is ‘like article’ to the product produced by the domestic industry.

D. Domestic industry and standing

7. The application has been filed by Futura Ceramics Private Limited. The applicant has claimed to be the sole producer of the subject goods in India. The applicant has further certified that it has not imported the subject goods nor is related to the exporters from the subject country or importers in India. The applicant has certified that it not related to any exporter or producer of the subject goods in China PR or an importer in India, either directly or indirectly within the meaning of Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules. However, the applicant has imported small volumes of the subject goods from the European Union. The Authority has examined the imports made by the applicant. It *prima facie* appears that the imports volumes by the applicant are small and not a significant amount. The applicant may be considered as constituting ‘domestic industry’ as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules. The application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.
8. In view of the same and based on the information available on record, the Authority is satisfied that the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' and satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).

E. Subject country

9. The country involved in the present sunset review investigation is China PR.

F. Likelihood of continuation or recurrence of dumpingNormal value

10. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules. The normal value has accordingly been determined in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules.
11. The applicant had proposed to determine the normal value on the basis of export price from the European Union to India. Alternatively, the applicant has proposed computation of normal value on the basis of price payable in India based on the cost of production in India and after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The Authority has, for the purpose of this initiation, considered the normal value for China PR based on cost of production and after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

Export price

12. The applicant has claimed the CIF price reported as per market intelligence for determination of export price. However, for the purpose initiation, the Authority has relied on the information provided by the applicant for computation of export price. The price has been adjusted with ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges.

Dumping margin

13. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Customs Tariff Act, 1975. It is noted that dumping margin is not only above *de minimis* level, but also significant. There is *prima facie* evidence that normal value of the subject goods is significantly higher than the net export prices, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being exported at dumped prices, thus, indicating continued dumping so as to justify initiation of the present investigation.

G. Likelihood of injury

14. There is *prima facie* evidence of dumping and consequent injury on account of increase in imports, significant share of imports in the Indian demand, suppressing effect of imports, losses suffered by domestic industry, low capacity utilization and low market and share of domestic industry despite the anti-dumping duty currently in force. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows continuation of dumping of subject goods from the subject country, and continuation of injury to domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty.

H. Initiation of sunset review investigation

15. And therefore, on the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

I. Period of Investigation (POI)

16. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2021 to March 2022. The injury investigation period will cover the periods 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the period of investigation. The data beyond period of investigation may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

J. Procedure

17. The present review covers all aspects of the final findings of the original investigations published vide Notification No. 14/47/2016-DGAD dated 26th March 2018. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

K. Submission of information

18. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
19. The known exporters, their Government through their Embassy in India, the importers, and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 18 above.
21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
22. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

L. Time-Limit

23. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in, within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limit.

M. Submission of information on confidential basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
27. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
28. The confidential version shall contain all the information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending

upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is that either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

33. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

O. Non-cooperation

34. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority